MPPSC भर्ती में बड़ा खेल! CAG की रिपोर्ट से मचा हड़कंप, युवाओं का इंतज़ार बढ़ा

मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है।भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)की ताजा रिपोर्ट ने प्रदेश की भर्ती प्रक्रिया की पोल खोलकर रख दी है। रिपोर्ट के अनुसार,मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)और संबंधित सरकारी विभागों के बीच तालमेल की इतनी भारी कमी है कि योग्य उम्मीदवार सालों से अपनी नियुक्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं।

CAG रिपोर्ट के अनुसार, 2018 से 2023 के बीच 44 प्रस्तावित परीक्षाओं में से 16 का विज्ञापन तक जारी नहीं हो सका। विभागों ने खाली पदों की जानकारी देने में 68 महीने तक की देरी की, जिससे भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह चरमरा गई है।

CAG की इस रिपोर्ट ने सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कहाँ हुई सबसे बड़ी लापरवाही और इसका युवाओं पर क्या असर पड़ा:

>> विभागों की सुस्ती:ऊर्जा विभाग, जेल विभाग और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी जैसे महत्वपूर्ण विभागों ने 101 खाली पदों की जानकारी भेजने में31 से 68 महीनेका समय लिया।

>> परीक्षाओं का संकट:साल2018 से 2023के बीच कुल 44 परीक्षाएं होनी थीं, लेकिन इनमें से केवल28 परीक्षाएंही आयोजित हो सकीं।

>> विज्ञापन में देरी:आयोग द्वारा जारी किए गए 94 विज्ञापनों में से 30 विज्ञापनों को जारी करने में औसतन136 दिनोंका समय लगा, जो प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।

सबसे ज्यादा विवादउच्च शिक्षा विभागमें सहायक प्राध्यापक के पदों को लेकर रहा। यहाँ की स्थिति बेहद चिंताजनक रही:

रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि आरक्षण नीति को लेकर कोई स्पष्ट आंतरिक व्यवस्था नहीं थी, जिसके कारण नियुक्तियां कानूनी विवादों में उलझती रहीं।दिव्यांगों के आरक्षणको लेकर आपत्तियां उठने के बावजूद समय पर सुधार नहीं किया गया।

सुधार के लिए क्या है सुझाव?

>> CAG ने मध्यप्रदेश शासन कोकेरल लोक सेवा आयोग (Kerala PSC Model)को अपनाने की सलाह दी है।

>> केरल मॉडल में भर्ती के लिएएक माह की समय सीमानिर्धारित है, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और तेज होती है।

>> सामान्य प्रशासन विभाग अब एकऑनलाइन पोर्टलविकसित कर रहा है, जिससे रिक्त पदों की जानकारी सीधे अपलोड होगी और विज्ञापनों में होने वाली देरी खत्म होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

मुख्य समस्या विभागों और आयोग के बीच समन्वय की कमी है, जिसके कारण रिक्त पदों की जानकारी समय पर नहीं मिलती और विज्ञापन जारी करने में महीनों की देरी होती है।

सरकार एक डिजिटल पोर्टल विकसित कर रही है जिससे विभाग रिक्त पदों की जानकारी ऑनलाइन अपलोड करेंगे, जिससे विज्ञापन प्रकाशन की

प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

Reference:Comptroller and Auditor General of India (cag.gov.in)